दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स हरियाणा

मई (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- 22 नए सेक्टर, चार मेडिकल कॉलेज और तीन महिला हॉस्टल के लिये मिलेगी ज़मीन 3
- टीबी की जाँच रिपोर्ट के लिये देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू 3
- 'ई-अधिगम' योजना 4
- हरियाणा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, 2022 4
- हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) का नया अध्यक्ष नियुक्त 5
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 5
- ज़िला सुशासन सूचकांक 6
- नूँह ज़िले के फतेहपुर गाँव में वाहन स्क्रैपिंग फेसिलिटी सेंटर का उद्घाटन 6
- रोहतक में स्थापित होगा पहला टेट्रापैक प्लांट 7
- ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के संदर्भ में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7
- ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के संदर्भ में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7
- प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हरियाणा में पहला वन अनुसंधान संस्थान 8
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 के पोस्टर का विमोचन 8
- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग 9
- आईएमटी खरखौदा 9
- गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिये तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित 10
- दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 10
- हरियाणा-दिल्ली जल विवाद 11
- हरियाणा वन विभाग की तरफ से हर गाँव में लगाए जाएंगे पौधे 11
- राष्ट्रीय कृमि मुक्त सप्ताह 11
- इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 12
- अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी 4.69 किलोमीटर लंबी सुरंग 12
- आस' ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत 13
- डिजिटल लर्निंग के तहत ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का आयोजन 13
- डैफलिंपिक्स, 2021 में जीते एथलीटों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित 14

नोट :

हरियाणा

22 नए सेक्टर, चार मेडिकल कॉलेज और तीन महिला हॉस्टल के लिये मिलेगी ज़मीन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने अपनी आय में बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य के 22 ज़िलों में 22 नए सेक्टर बनाने के साथ-साथ चार मेडिकल कॉलेजों व तीन महिला हॉस्टल के लिये ज़मीन देने की कार्ययोजना तैयार की है।

प्रमुख बिंदु

- इन नए सेक्टरों के विकसित होने के बाद लोगों को अच्छी रिहायश के लिये मारामारी नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें आसानी से पॉश इलाकों में प्लॉट उपलब्ध हो सकेंगे।
- राज्य के पाँच प्रमुख ज़िलों- फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक और हिसार में भूमि अधिग्रहण और मुआवज़ा वितरण में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिये सरकार ने ज़िला भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त किये हैं।
- एचएसवीपी द्वारा पंचकूला, फतेहाबाद, दादरी व पलवल में बनने वाले चार मेडिकल कॉलेजों के लिये करीब 50 एकड़ ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके अलावा एचएसवीपी की योजना भिवानी, सिरसा और रेवाड़ी में महिला हॉस्टल बनाने की है। इसके लिये भी ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी।
- गुरुग्राम व हिसार में कॉमर्शियल व रिहायशी साइट की ऑनलाइन नीलामी के लिये 10 व 11 मई की तिथि निर्धारित की गई है।
- एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने प्राधिकरण की आय में बढ़ोतरी तथा लोगों को अधिक-से-अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का खाका तैयार के लिये 22 मई को एचएसवीपी की 13 ऑनलाइन सर्विस शुरू होंगी।
- हालाँकि एचएसवीपी की कई सेवाएँ पहले से ऑनलाइन हैं, लेकिन इनमें बढ़ोतरी की जा रही है, ताकि लोग घर बैठे लाभान्वित हो सकें।

टीबी की जाँच रिपोर्ट के लिये देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू

चर्चा में क्यों ?

4 मई, 2022 को हरियाणा के हिसार ज़िले में टीबी की जाँच के लिये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह पायलट प्रोजेक्ट नौ महीने के लिये शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- डिप्टी सीएमओ डॉ. अनामिका ने बताया कि देश में पहली बार शुरू किये गए इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मरीज़ की पहचान जल्दी करना है।
- टीबी की जाँच रिपोर्ट अब 5 दिन में नहीं, बल्कि एक दिन में ही मिलेगी, जिससे संक्रमण पर अंकुश लगेगा।
- आईडीडीएस एजेंसी इस प्रोजेक्ट को लेकर आई है तथा यूएस एंड संस्था जाँच का खर्च उठा रही है।
- पहले टीबी की जाँच की जाती थी, तो 100 में से 60 प्रतिशत ही लोग पकड़ में आते थे। ऐसे में ये लोग टीबी का संक्रमण फैलाते थे।
- आईडीडीएस एजेंसी ने थायरो केयर लैब से करार किया है। दो संस्थाएँ तीन और छह महीने में सर्वे करेंगी। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। अगर रिपोर्ट सकारात्मक आती है, तो इस प्रोजेक्ट को पूरे देश में शुरू किया जाएगा।

नोट :

'ई-अधिगम' योजना

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के रोहतक ज़िले से 'ई-अधिगम' योजना का शुभारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किये।
- राज्य के 119 स्थानों पर यह टैबलेट वितरण समारोह आयोजित किया गया है।
- उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में तकनीक को अपनाकर शिक्षा देने की योजना को देश भर में लागू करने के लिये वर्ष 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, जबकि हरियाणा सरकार 2025 तक इसे लागू करने को लेकर संकल्पित है।
- हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, जिसने 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट देने की घोषणा की है।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा अपने बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। इस बार के बजट में अकेले 20 हज़ार करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किये जा रहे हैं।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिये सरकार दो टास्क फोर्स बनाने जा रही है। एक टास्क फोर्स स्कूलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, चारदीवारी, सुंदरता, स्वच्छता, रास्ते, पानी और शौचालय सहित अन्य ज़रूरी आवश्यकताओं पर काम करेगी तो दूसरी टास्क फोर्स स्कूलों में फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

हरियाणा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, 2022

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, 2022' को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति का उद्देश्य एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के विकास के लिये पूर्णतया पारिस्थितिक तंत्र सृजित करने पर बल देते हुए आगामी पाँच वर्षों में एक बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना तथा लगभग 25 हज़ार लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित कर हरियाणा को देश के अग्रणी एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- इस नीति में ऑटो घटकों और ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।
- इस नीति के माध्यम से हरियाणा सरकार राज्य में मानव पूँजी विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कदम, जैसे- पाठ्यक्रम विकास, अनुसंधान एवं नवाचार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, एयरोस्पेस एवं रक्षा विश्वविद्यालय और फ्लाइंग स्कूल की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है।
- यह नीति हरियाणा में एक विश्वस्तरीय एमआरओ बनाने की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। साथ ही यह नीति एमएसएमई क्षेत्र के विकास और इसके व्यवसाय के विकास पर विशेष जोर देती है।
- राज्य सरकार हरियाणा में मौज़ूदा हवाई अड्डों या नए स्थानों पर नई एमआरओ सुविधाओं की स्थापना के प्रस्तावों को सुविधाजनक और प्रोत्साहित करेगी।
- राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये क्लस्टर विकास, बाज़ार संबंधों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी ढाँचे व प्रौद्योगिकी तक पहुँच बढ़ाने, नियामक सरलीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट तथा वित्तीय प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।
- इस नीति के तहत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं-
- एफसीआई की 125 प्रतिशत की सीमा तक डी श्रेणी के ब्लॉकों में 10 वर्षों के लिये शुद्ध एसजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- सी श्रेणी के ब्लॉकों में 8 वर्षों के लिये शुद्ध एसजीएसटी की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नोट :

- बी श्रेणी के ब्लॉकों में 7 वर्षों के लिये शुद्ध एसजीएसटी की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- बी, सी और डी ब्लॉकों और हरियाणा में सभी हवाईपट्टियों (हिसार एयपोर्ट को छोड़कर) की 10 किलोमीटर की परिधि में, स्थाई पूँजी निवेश (एफसीआई) का 5 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है।
- एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, हिसार और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार (एमएएएच) के आस-पास 10 किलोमीटर की परिधि में स्थायी पूँजी निवेश (एफसीआई) का 5 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपए, निवेश किया जाएगा।
- बी, सी और डी ब्लॉक में 40,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक वेतन वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये 48,000 रुपए प्रतिवर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- बी, सी और डी ब्लॉकों में एयरोस्पेस एवं डिफेंस इकाइयाँ भूमि की खरीद की तारीख से 5 साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद बिक्री/पट्टा विलेख पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये पात्र होंगी।
- बी, सी और डी ब्लॉक में 10 साल के लिये बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।
- उच्च शिक्षा में एविएशन/एयरोस्पेस से संबंधित कोर्स करने वाले छात्रों के लिये एक क्रेडिट गारंटी योजना की पेशकश की जाएगी।
- राज्य में अनुसंधान और नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत इकाइयों को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक प्रदान की जाएगी।

हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) का नया अध्यक्ष नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2022 को हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- सिंघल ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक डॉ. हनीफ कुरैशी की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया।
- गौरतलब है कि सिंघल रूड़की विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हैं और उन्होंने सरकारी व निजी क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न संगठनों में प्रशासक, योजनाकार और सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।
- नव नियुक्त महानिदेशक सिंघल ने पदभार संभालते ही हरियाणा में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों को गति देने के लिये खेतों में धान की पराली जलाने की समस्या से निपटने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हरियाणा और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना को कार्यरूप देने की बात की है।
- इसके अलावा उन्होंने कहा कि छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से सौर ऊर्जा का दोहन करने के प्रयास किये जाएंगे। इन प्रयासों से न केवल रोज़गार सृजन होगा, बल्कि राज्य की स्वच्छ और हरित अर्थव्यवस्था में भी योगदान होगा।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2022 को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सीजन का शानदार और भव्य आगाज़ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस लॉन्च कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय खेल, युवा मामले और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर (मस्कट), लोगो, जर्सी और थीम गीत लॉन्च किया गया।
- 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021' का आयोजन 4 जून से 13 जून, 2022 तक राज्य सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में 25 तरह के खेल आयोजित होंगे, जिनमें पाँच पारंपरिक खेल, जैसे- गतका, कलारीपयट्टू, थांग-ता, मलखंब और योगासन शामिल हैं। ये खेल पाँच स्थानों पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 में 8,000 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने बताया कि इन खेलों के आयोजन हेतु ताऊ देवीलाल खेल परिसर, पंचकूला में हॉकी एस्ट्रोटर्फ, वॉलीबॉल इंडोर हॉल व बास्केटबॉल इंडोर हॉल तथा अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडोर स्वीमिंग पूल का निर्माण करवाया गया है, साथ ही सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन हॉल आदि का नवीनीकरण करवाया गया है।

ज़िला सुशासन सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य में सर्वांगीण विकास के लिये ज़िला सुशासन सूचकांक तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस सूचकांक के माध्यम से ज़िला स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन कर एक राज्यस्तरीय विकास सूचकांक तैयार किया जा सकेगा।
- यह ज़िलों के बीच विकास के संबंध में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के विकास सूचकांक में वृद्धि होगी।
- यह सूचकांक जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा निर्मित सूचकांक के अनुरूप होगा।
- गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 10 सेक्टरों पर 58 विकास सूचकांक तैयार किये गए हैं।
- ये 10 सेक्टर्स हैं- कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक अवसंरचना और सुविधाएँ, समाज कल्याण और विकास, वित्तीय समावेशन, न्याय और जनता सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रीय शासन।

नूँह ज़िले के फतेहपुर गाँव में वाहन स्क्रैपिंग फेसिलिटी सेंटर का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने नूँह ज़िले के फतेहपुर गाँव में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फेसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी से प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी।
- इस नीति से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कॉपर, स्टील, एल्युमीनियम, रबड़ और प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति (Vehicle Scrapping Policy) की घोषणा की गई थी, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-
- पुन: पंजीकरण कराने से पूर्व 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों और 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों को एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।
- पुराने वाहनों का परीक्षण स्वचालित फिटनेस केंद्र में किया जाएगा, यहाँ वाहनों का फिटनेस टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर किया जाएगा।
- राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे निजी वाहनों के लिये 25% तक और व्यावसायिक वाहनों हेतु 15% तक रोड-टैक्स में छूट प्रदान करें ताकि पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने तथा अनफिट वाहनों को हटाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- वाहन निर्माताओं द्वारा 'स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट' दिखाने वालों को नई गाड़ी लेने पर 5% की छूट दी जाएगी, साथ ही नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
- 15 वर्ष या इससे पुराने वाहनों के पुन: पंजीकरण शुल्क को बढ़ाकर ऐसे वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।

नोट :

रोहतक में स्थापित होगा पहला टेट्रापैक प्लांट

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2022 को हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि तरल दूध, फलों के रस और किण्वित दूध उत्पादों की पैकिंग के लिये हरियाणा राज्य का पहला टेट्रापैक संयंत्र रोहतक में स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 125 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले इस प्लांट से लिक्विड उत्पादों का लंबे समय तक भंडारण कर उन्हें सुरक्षित रखा जा सकेगा। रोहतक वीटा प्लांट की वर्तमान में उत्पादन क्षमता 4.5 लाख लीटर प्रतिदिन है।
- डॉ. बनवारी लाल ने रोहतक के वीटा प्लांट में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किये जाने वाले बटर डीप फ्रीज़र की आधारशिला रखने के उपरांत कहा कि वीटा प्लांट में सफेद मक्खन के भंडारण के लिये बटर डीप फ्रीज़र लगने से एक हज़ार मीट्रिक टन मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा।
- यह प्लांट दूध, वीटा घी, वीटा मक्खन, दही, नमकीन लस्सी, छाछ, पनीर व बर्फी इत्यादि के साथ-साथ भारतीय सेना को वीटा घी व दूध की आपूर्ति तथा मिड-डे-मिड मील, आँगनबाड़ी योजना व खेल योजनाओं के अंतर्गत बच्चों व खिलाड़ियों की दूध की मांग को पूरा करने के लिये सुगंधित मीठे दूध पाउडर की आपूर्ति भी की जा रही है।
- इस प्लांट में 4 करोड़ रुपए की लागत से एक नया एसएफएसएमपी संयंत्र की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है।
- इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि पलवल, कैथल तथा महम सहकारी चीनी मिलों में चीनी के साथ-साथ गुड़ व शक्कर का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं शाहबाद चीनी मिल में एथनॉल प्लांट शुरू किया गया है।

ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के संदर्भ में दूसरा गोलमेज सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2022 को हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किये जाने वाले ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के लिये प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स एवं रियल एस्टेट केंद्रित फंड की तलाश के संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मुंबई में दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, जो सरकार की एक नोडल एजेंसी है, के तत्त्वावधान में विकसित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से गुरुग्राम को केंद्रीय व्यापार ज़िले के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और भावी उन्मुख उद्योगों, निम्न कार्बन हरित बुनियादी ढाँचे, सुगम जीवन, लोगों के कौशल विकास और रोज़गार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस अवसर पर हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता ने बताया कि यह एक मिश्रित भूमि उपयोग परियोजना है, जिसे निर्माणाधीन 8-लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ गुरुग्राम में सेक्टर 36बी, 37ए और 37बी में विकसित हो रहे आवासीय और वाणिज्यिक केंद्र में लगभग 1003 एकड़ क्षेत्र पर 'एक शहर के भीतर शहर' के रूप में विकसित करने की कल्पना है।

ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के संदर्भ में दूसरा गोलमेज सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2022 को हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किये जाने वाले ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के लिये प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स एवं रियल एस्टेट केंद्रित फंड की तलाश के संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मुंबई में दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन आयोजित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, जो सरकार की एक नोडल एजेंसी है, के तत्त्वावधान में विकसित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से गुरुग्राम को केंद्रीय व्यापार ज़िले के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और भावी उन्मुख उद्योगों, निम्न कार्बन हरित बुनियादी ढाँचे, सुगम जीवन, लोगों के कौशल विकास और रोज़गार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस अवसर पर हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक विकास गुप्ता ने बताया कि यह एक मिश्रित भूमि उपयोग परियोजना है, जिसे निर्माणाधीन 8-लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ गुरुग्राम में सेक्टर 36बी, 37ए और 37बी में विकसित हो रहे आवासीय और वाणिज्यिक केंद्र में लगभग 1003 एकड़ क्षेत्र पर 'एक शहर के भीतर शहर' के रूप में विकसित करने की कल्पना है।

प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हरियाणा में पहला वन अनुसंधान संस्थान

चर्चा में क्यों ?

15 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर के जगाधरी में राज्य में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिये 50 करोड़ रुपए की लागत से पहला वन अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- यह घोषणा मुख्यमंत्री ने जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए की। इससे पूर्व उन्होंने लगभग 334 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सढ़ोरा के 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल करने, किशनपुरा गाँव में 14 एकड़ ज़मीन पर नया कॉलेज भवन बनाने, फारुखपुर स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने के साथ-साथ ज़िला यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये कुल 680 करोड़ रुपए देने की घोषणाएँ भी की।
- मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा हर ब्लॉक में 50 से 100 एकड़ में एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की योजना है, ताकि नौजवानों को रोज़गार के अवसर मिले। यमुनानगर के पाँचों खंडों में पाँच क्लस्टर बनाए जाएंगे।
- उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के आसपास के ज़िलों, यानी- पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला तथा कुरुक्षेत्र में गुरुग्राम की तर्ज़ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाएंगे।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 के पोस्टर का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

15 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खेल एवं युवा मामले के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 के पोस्टर का विमोचन तथा इसके प्रमोशनल सांग के ऑडियो वर्जन को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रमोशनल सांग के ऑडियो वर्जन के बाद जल्द ही वीडियो वर्जन को लॉन्च किया जाएगा।
- इस सांग को हरियाणा और बॉलीवुड के कलाकारों ने मिलकर तैयार किया है और इस गीत को मुख्यमंत्री के ओएसडी प्रचारक गजेंद्र फोगाट और नवीन लांबा ने लिखा है।
- गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 का आयोजन 4 से 13 जून, 2022 तक किया जाएगा। इनमें अंडर 18 के 25 खेलों में 5 भारतीय खेल भी शामिल हैं।
- ये खेल पंचकूला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किये जाएंगे। इन खेलों में देश भर के लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों में हरियाणवी संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के हीरोज़ की कहानी तथा प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का परिचय प्रदर्शनी में दर्शाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके।
- हरियाणा में होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2021 के चौथे संस्करण में जय और विजय के साथ इस बार दर्शकों को हरियाणा का अपना मस्कट धाकड़ भी देखने को मिलेगा, जो हरियाणा के दूध-दही के खाने और यहाँ की खेल संस्कृति का परिचायक बनेगा।

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2022 को हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा 1 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के दौरान राशन कार्ड जारी करने के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित मामलों में हुई देरी के संबंध में कार्यवाही करते हुए एक मामले में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 31 जुलाई, 2014 को जारी अधिसूचना के तहत किया गया था।
- यह आयोग हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 12(1) और (2) के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
- इस आयोग में 1 मुख्य आयुक्त और अधिकतम 4 आयुक्त होंगे, जो हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे।
- एचआरटीएस अधिनियम, 2014 ने लोगों को एक प्रभावी सेवा वितरण तंत्र के माध्यम से परेशानीमुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाने का अधिकार दिया है।

आईएमटी खरखौदा

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि 'मारुति' हरियाणा में अपना तीसरा संयंत्र स्थापित कर रही है। इसके लिये एमएसआईएल ने आईएमटी खरखौदा में 800 एकड़ भूमि की खरीद की है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 'मारुति' ने 1983 में गुडगाँव (अब गुरुग्राम) में अपना पहला कार संयंत्र स्थापित करने के बाद मानेसर में एक अन्य विनिर्माण सुविधा और रोहतक में एक अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करके हरियाणा में अपनी विनिर्माण सुविधाओं का लगातार विस्तार किया है।
- आईएमटी खरखौदा सोनीपत स्थित विश्वस्तरीय आधारभूत अवसंरचना के साथ एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप है, जो लगभग 3,217 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है।
- यह रणनीतिक रूप से पश्चिमी परिधीय (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे और राज्यीय राजमार्ग-18 के साथ लगती दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित है।
- यह हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किये गए/ किये जा रहे औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में से एक है।
- गौरतलब है कि एक विशेष स्थान पर 1500 एकड़ क्षेत्र से ऊपर विकसित एक औद्योगिक संपत्ति (Industrial Estate) को एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) के रूप में परिभाषित किया गया है।

नोट :

गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिये तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित करने के लिये तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा इंडस्ट्री लीडर्स व रियल एस्टेट क्षेत्र से बड़े डिवलेपर्स ने भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि गुरुग्राम में ऐसी ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना है, जो कि विश्वस्तरीय आइकॉनिक सिटी हो। इसमें सभी प्रकार की वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- शहरी विकास के पहले से बने नार्म्स की बजाय लोगों की मांग के अनुसार मिलने वाले सुझावों के आधार पर इस सिटी की प्लानिंग की जाएगी।
- इसमें विश्व स्तर के प्लानर और डिज़ाइनरों को शामिल किया जाएगा। इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर्स को शामिल करते हुए इस ग्लोबल सिटी को विश्वस्तरीय स्वरूप दिया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी मिक्स लैंड यूज़ टाउनशिप एक 'सिटी इन ए सिटी'होगी जिसमें प्रेरक कार्यक्षेत्र और बीस्पोक सिटी सैंट्रिक लिविंग की सुविधा होगी।
- सर्विस इंडस्ट्री के लिये एक हब के रूप में गुरुग्राम की क्षमता का दोहन करने के लिये इस ग्लोबल सिटी की कल्पना की गई है।
- यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी) के रूप में होगी जहाँ पर काम करने, खेलने, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिये आवश्यक हर चीज़ होगी।
- गौरतलब है कि गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी के नाम से विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे और जीवन की उच्च गुणवत्ता के साथ एक कारोबारी माहौल की आकांक्षाओं के साथ विकसित करने की राज्य सरकार की योजना है।
- इसे एक हज़ार एकड़ से ज़्यादा भूमि पर विकसित किया जाएगा जिसमें कार्यालय स्थान, आवासीय टावर, अस्पताल, होटल, प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र आदि होंगे ताकि एक जीवंत लाइव-वर्क-रिलेक्स ईको सिस्टम बनाया जा सके।

दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

19 मई, 2022 को पर्यावरण संरक्षण के लिये किये गए उल्लेखनीय कार्यों हेतु हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने दर्शन लाल जैन राज्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के लिये नामांकन आमंत्रित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- इन पुरस्कारों के लिये संगठन/संस्थान, सरकारी विभाग, व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन, स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थाएँ, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अनुकरणीय कार्य किया है, लिये पात्र होंगे।
- नामांकन के पश्चात् स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयनित लोगों को दो पुरस्कार दिये जाएंगे और उन्हें प्रशस्ति-पत्र तथा 3 लाख रुपए व 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
- यह पुरस्कार चयनित उम्मीदवारों को 5 जून, 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में वितरित किये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2022 में हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे- प्रदूषण नियंत्रण (जल और वायु), प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विभिन्न प्रकार के कचरे के प्रबंधन और पर्यावरण मुद्दों पर आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु किये गए उल्लेखनीय प्रयासों के लिये हरियाणा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर एक नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की थी।

नोट :

हरियाणा-दिल्ली जल विवाद

चर्चा में क्यों ?

20 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली सरकार द्वारा उसके हिस्से का पानी नहीं देने के आरोप पर कहा कि हरियाणा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और प्रदेशों के समझौतों के अनुसार दिल्ली को उसके हिस्से का 1049 क्यूसिक पूरा पानी दे रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वज़ीराबाद/चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिये पानी की आपूर्ति करता आ रहा है।
- गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 29 फरवरी, 1996 को हरियाणा सरकार को निर्देश दिये थे कि दिल्ली को प्रतिदिन 330 क्यूसिक अतिरिक्त पानी दिया जाए। इससे पहले दिल्ली का पानी में हिस्सा प्रतिदिन 719 क्यूसिक था।
- ध्यातव्य है कि गत वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा के विरुद्ध याचिका दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया गया था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में अपने निर्णय में दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वज़ीराबाद प्लांट में हमेशा पानी का उच्च स्तर बनाए रखने का निर्देश दिया था। जबकि दिल्ली सरकार के अनुसार हरियाणा द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

हरियाणा वन विभाग की तरफ से हर गाँव में लगाए जाएंगे पौधे

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2022 को हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल ने बताया कि प्रदेश के हर गाँव को ग्रीन बनाने के लिये इस वर्ष प्रदेश के हर गाँव में वन विभाग की तरफ से पंचायत की खाली पड़ी ज़मीन पर पौधे लगाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- वन मंत्री कंवरपाल ने यह जानकारी कुरुक्षेत्र में हरियाणा पर्यावरण सोसायटी (एचईएस) द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर ब्रह्मसरोवर के वीआईपी घाट पर हुए पौधारोपण अभियान के शुभारंभ के दौरान दी।
- वन मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में वन विभाग की तरफ से 20 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।
- कंवरपाल ने कहा कि गाँव में पंचायत की जितनी ज़मीन खाली मिलेगी, उतनी ज़मीन पर पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के हर गाँव के शिव धामों में 10 से लेकर 100 पौधे लगाए जाने के कार्य को भी किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृमि मुक्त सप्ताह

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्त सप्ताह की शुरुआत की गई। यह 29 मई तक मनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों, मान्यताप्राप्त विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों-प्ले स्कूल में अध्ययनरत् तथा नामांकित एवं विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को पेट के कीड़े मारने की एल्बेंडाजोल की टेबसेट नि:शुल्क खिलाई जाएगी।
- अभियान के तहत जो भी बच्चे 23 से 26 मई के बीच दवा खाने से वंचित रह जाएंगे, उन बच्चों को 27 से 29 मई तक घर-घर जाकर दवा दी जाएगी।
- इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिये स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से मिलकर आपसी तालमेल से कार्य करेंगे।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर हर 6 महीने में एक साल से 19 साल तक के बच्चे के स्वास्थ्य को सुधारने के लिये पेट के कीड़े मारने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाती है, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे।

नोट :

इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि नांगल चौधरी (महेंद्रगढ़) में 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में उत्तर भारत में सबसे बड़े इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब के रूप में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यह बात हरियाणा से गुज़रने वाली फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में कही।
- उन्होंने इस इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को दिल्ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट करने के लिये डीएफसीसीआईएल द्वारा कनेक्टिंग लाइन बनाए जाने के कार्य में तेज़ी लाने के निर्देश भी दिये।
- हरियाणा से 246 किमी. लंबाई के ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर गुजरेंगे, जिनके बनने से एक ओर जहाँ यातायात में सुगमता होगी तो वहीं ये कॉरिडोर हरियाणा के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे।
- 1506 किमी. लंबा वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा और 177 किमी. स्ट्रेच हरियाणा में बनेगा।
- इसी प्रकार, 1875 किमी. लंबा ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुज़रेगा और 72 किमी. स्ट्रेच हरियाणा में बनेगा।

अरावली की पहाड़ियों से निकलेगी 4.69 किलोमीटर लंबी सुरंग

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2022 को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल ने बताया कि अरावली की पहाड़ियों में69 किमी. लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अरावली की पहाड़ियों पर बनने वाली यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल (मनाली से लाहौल स्पीति घाटी तक02 किमी.) की तरह होगी।
- यह सुरंग कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे के समानांतर7 किमी. लंबे हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर में बनाई जाएगी।
- हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड करवाएगी।
- यह कॉरिडोर कुंडली से मानेसर तक नए विकसित हो रहे औद्योगिक व रिहायशी क्षेत्रों के लिये लाइफ लाइन बनेगा, साथ ही पहाड़ियों के बीच से निकलने वाली69 किमी. लंबी सुरंग दिल्ली-एनसीआर के लिये दर्शनीय स्थल होगा।
- हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुरंग निर्माण के लिये निविदा प्रक्रिया चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक पूरी करने लेने का दावा किया है।
- इस आशय से हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुरंग निर्माण क्षेत्र की 20 कंपनियों के अधिकारियों के साथ मंत्रणा की है।
- हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश अग्रवाल का कहना है कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत 30 माह की समयावधि में हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर सुरंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
- गौरतलब है कि अरावली संसार की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो 692 किमी. लंबी है। इसका विस्तार हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली तक है।

नोट :

आस' ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में 'आस' यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम की शुरुआत की। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 192 सेवाएँ ऑनबोर्ड हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किये गए 'आस' के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू किया है।
- सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयावधि की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाने व उन्हें जागरूक करने के लिये यह निर्णय लिया गया है।
- मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिये इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है, ताकि नागरिकों के कार्य एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर हों।
- उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को एक सप्ताह के अंदर ही अपने विभागों की सेवाओं को अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनबोर्ड करने के निर्देश दिये।

डिजिटल लर्निंग के तहत ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

27 मई, 2022 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कँवर पाल ने राज्य के पंचकूला ज़िले में राष्ट्रस्तरीय डिजिटल लर्निंग ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उदघाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्लेटफार्म को आगे बढ़ाने की दिशा में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कँवर पाल ने समिट का उद्घाटन करते हुए कोविड के बाद अध्यापन व अध्ययन में सूचना प्रोद्यौगिकी के महत्त्व के पहलुओं पर भी चर्चा की।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल के बच्चों को आईटी के टूल किट वितरित किये जा रहे हैं तथा राज्य के बच्चे किसी भी दृष्टि से कमज़ोर न रहें, इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि कार्यशाला में जारी की गई डिजिटल लर्निंग की पुस्तिका एक उपयोगी दस्तावेज़ है, जिसमें विश्व भर में हो रहे शिक्षा परिवर्तनों की जानकारी दी गई है।
- नई शिक्षा नीति, 2020 को देश में सबसे पहले क्रियान्वित करने की हरियाणा ने पहल की है और कहीं-न-कहीं आज का समिट भी उसी का हिस्सा है।
- शिक्षा मंत्री ने डिजिटल लर्निंग सोल्यूशन, डिजिटल क्लासरूम सोल्यूशन, डिजिटल बोर्ड सोल्यूशन, डिजिटल लैंग्वेज लैब सोल्यूशन, सिक्यूरिटी एंड सर्विलॉन्स सोल्यूशन, स्कूलनैट, लर्निंग फॉर लाइट पर लगाई गई ई-एक्पो का अवलोकन भी किया।
- इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण नीति लागू की थी, जो शिक्षा विभाग में आईटी के युग का एक क्रांतिकारी कदम था।
- विभाग द्वारा 'अवसर' ऐप लॉन्च किया गया है। विद्यार्थियों का असेसमेंट व ई-रिपोर्ट कार्ड भी इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कोविड के दौरान इस 'अवसर' ऐप को बनाया गया, जो बड़ा ही कारगर सिद्ध हुआ।
- कार्यशाला में शिक्षा मंत्री ने ई-लेट में बेहतर प्रदर्शन के लिये पश्चिम बंगाल को कर्मभूमि तथा हरियाणा शिक्षा विभाग की एकेडमिक सेल तथा आशीष धाम को सम्मानित भी किया।

नोट :

डैफलिंपिक्स, 2021 में जीते एथलीटों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय सम्मान समारोह के दौरान डैफलिंपिक्स एथलीटों को लगभग 6 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 1 मई से 15 मई तक ब्राज़ील में डैफलिंपिक्स, 2021 खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें देश के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए कुल 16 पदकों में से 4 स्वर्ण सहित 6 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं।
- इसीलिये हरियाणा को भारत की पदक फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के 65 एथलीटों में से 15 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं।
- मुख्यमंत्री ने रोहित भाकर, महेश, दीक्षा डागर और सुमित दहिया को क्रमश: बैडमिंटन, गोल्फ और कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने के लिये 1.20-1.20 करोड़ रुपए के चेक भेंट किये गए। वहीं कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले अमित और वीरेंद्र सिंह को 40-40 लाख रुपए के चेक प्रदान किये।
- इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये प्रियंका, बलराम, योगेश डागर, निर्चिरा, अजय कुमार, कुलदीप शर्मा, आसिफ खान, अमन और शुभम वशिष्ठ को 2.5-2.5 लाख रुपए के चेक दिये।
- साथ ही मुख्यमंत्री ने 116 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चार अत्याधुनिक खेल सुविधा केंद्रों का भी लोकार्पण किया।
- इनमें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र, 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हॉकी एस्ट्रो-टर्फ और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एथलेटिक्स ट्रैक का नवीनीकरण शामिल है।
- मनोहर लाल ने कहा कि हमने ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने का प्रावधान किया है।
- मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने खिलाड़ियों को खेल की तैयारी के लिये 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि देने का प्रावधान किया है ताकि उन्हें अपनी तैयारी में कोई कठिनाई न हो।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये रोज़गार सुनिश्चित करने के लिये हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2018 लागू किये हैं।

नोट :